मोदी पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त कारण.....

पेज एक का शेष

एमिकस क्यूरी ने आगे कहा कि "श्री भट्ट बैठक में मौजूद थे या नहीं ये सवाल.....और श्री मोदी ने इस तरह का कोई एक बयान दिया था या नहीं....को केवल न्यायपालिका ही तय कर सकती है।"

रामचंद्रन के विचार में श्रीमती जाफरी की शिकायत में दो विशिष्ट किस्म की शिकायतें बहुत गंभीर थीं। पहली, 27 फरवरी 2002 की बैठक में पुलिस अधिकारियों को मोदी के निर्देश और दूसरी मुस्लिम विरोधी हिंसा के दौरान राज्य और अहमदाबाद सिटी पुलिस कंट्रोल रूम में दो कैबिनेट मंत्रियों की तैनाती शामिल थी। भट्ट की गवाही को खारिज करने के एसआईटी के आधार का एमिकस ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि "मेरे विचार में ऊपर दी गयी पृष्ठभूमि के बावजूद ऐसा नहीं लगता है कि एक सेवारत पुलिस अफसर बगैर किसी ठोस आधार के राज्य के मुख्यमंत्री मोदी के खिलाफ इतना गंभीर आरोप लगाएगा। इस तरह का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है जिससे ये स्थापित हो सके कि श्री भट्ट 27.02.2002 की बैठक में मौजूद नहीं थे।"

रामचंद्रन ने इस बात को चिन्हित किया कि एसआईटी ने वरिष्ठ अफसरों के शब्दों पर भरोसा किया जबकि अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में उसने कहा था कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। एसआईटी के मुताबिक कुछ अफसर बहुत पहले रिटायर हो गए और वो याददाश्त खोने का दावा कर रहे थे जैसा कि वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। कुछ दूसरों को रिटायरमेंट के बाद अच्छे खासे लाभ मिले। जिससे वो "मौजूदा मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञ थे लिहाजा उनकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।"

उसके बाद रामचंद्रन इस बात पर आते हैं कि उनके विचार से भट्ट क्यों उस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिए रहे होंगे। उस समय के दो वरिष्ठ इंटेलिजेंस अफसर आईबी चीफ जीसी रैगर और डिप्टी कमिश्नर (पोलिटिकल एंड कम्यूनल) पीसी उपाध्याय दोनों 27 फरवरी 2002 को छुट्टी पर थे। रैगर ने कहा था कि मोदी द्वारा बुलायी गयी पिछली दो बैठकों में भट्ट उनके साथ थे। हालांकि वो फाइल लेकर बाहर खड़े थे। "इसलिए ये बिल्कुल संभव है कि चीफ मिनिस्टर के आवास पर 27.02.2002 को बुलाई गयी बैठक में भट्ट को शामिल होने का निर्देश दिया गया हो। एसआईटी को दिए गए भट्ट के बयान और उनके फोन कॉल रिकार्ड्स में कोई विरोधाभास नहीं है। बैठक के महत्व और इमरजेंसी को देखते हुए तुलनात्मक रूप से भट्ट का जूनियर होना बैठक में शामिल होने के रास्ते में बाधा नहीं बनता है....संदर्भ एक इमरजेंसी बैठक है जिसे एक खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए एक छोटी नोटिस पर बुलाया गया है...."

अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में एसआईटी ने दो मंत्रियों आईके जडेजा और अशोक भट्ट की कंट्रोल रूम में तैनाती की बात को खारिज कर दिया था। उसके मुताबिक "इस बात की पूरी संभावना है कि उसको (उनकी मौजूदगी को) उनकी (मोदी की) मौन सहमति रही हो। फिर भी जांच टीम ने पाया कि श्री भट्ट (जिनका उस समय निधन हो गया था) की मौजूदगी को स्थापित नहीं किया जा सका। एसआईटी इस नतीजे पर भी पहुंची कि मंत्री/मंत्रीगण किसी भी रूप में पुलिस के कामों में दखलंदाजी नहीं किए थे।"

एमिकस ने मंत्री अशोक भट्ट की मौजूदगी को लेकर एसआईटी के बदले हुए वर्जन का विरोध किया और इस बात को चिन्हित किया कि एसआईटी की पहली रिपोर्ट खुद भट्ट के बयान पर आधारित थी जिसमें उन्होंने 28 फरवरी 2002 को कंट्रोल रूम का दौरा करने की बात को स्वीकार किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री की कंट्रोल रुम में मौजूदगी ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए काफी है। और ट्रायल के दौरान इस पहलू से परीक्षण बहुत जरूरी है।

रामचंद्रन ने कहा था कि हालांकि इस बात के साक्ष्य मौजूद नहीं हैं कि दोनों मंत्री मोदी के 27 फरवरी 2002 के कथित मुस्लिम विरोधी निर्देशों पर काम किए थे। लेकिन "पुलिस कंट्रोल रूम में दो राजनीतिक शख्सियतों की मौजूदगी जिनका गृह विभाग से कोई रिश्ता नहीं है, इस बात का परिस्थिति जन्य प्रमाण है कि मुख्यमंत्री उन्हें निर्देश दे रहा है या फिर उसकी इजाजत दिए हुए है। जैसा कि पहले ही एसआईटी चीफ ने खुद ही इस बात को पाया है कि कंट्रोल रूप में उनकी मौजूदगी के पीछे कम से कम मुख्यमंत्री की मौन सहमति थी।"

FASHION.IN

Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top, T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट

एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100,500 रुपये 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

नोटबंदी को श्रद्धांजलि

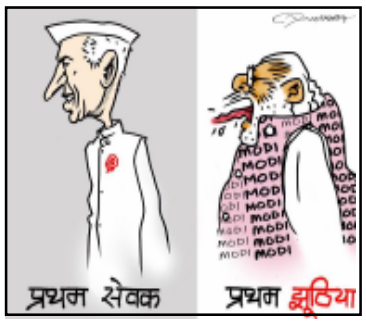

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मजदूर मोर्चा के 11-17 नवम्बर 2018 के अंक में ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व सामाजिक ज्वलंत मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवम्बर 2016 को 1000 व 500 रूपए के नोटों को बंद करने तथा 2000 व 500 रूपए के नए नोटों के चलन की घोषणा करते हुए नोटबंदी के लक्ष्य घोषित किए - काले धन पर चोट, आतंकवाद की फडिंग रोकना और नकली नोटों की समस्या से छुटकारा पाना। परन्तु जल्दी ही नोटबंदी के घोषित लक्ष्य असफल नजर आने पर मोदी सरकार ने अपना गोलपोस्ट शिफ्ट करने में देर नहीं लगाई। नकद भुगतान की जगह कैशलैस भारत, इलैक्ट्रोनिक लेन-देन, पेटीएम आदि से भुगतान करने का प्रचार किया जाने लगा। नोटबंदी की रही सही कसर जीएसटी ने कर दी, जिसके कारण बाजार में धन की कमी हो गई और व्यापार व उद्योग धंधे चौपट हो गए?

'धन तेरस पर धन को तरसे उर्फ मोदी को श्रद्धांजलि नोटबंदी बरसी पर.....' में धन तेरस के दिन दिल्ली व फरीदाबाद के बाजार में किए गए सर्वे की रिपोर्ट में नोटबंदी व जीएसटी की घातक चोट के कारण चौपट हुए व्यापार व धंधे की असली दशा को उजागर किया गया है। धन की कमी के कारण व्यापारियों व कारोबारियों को गहन संकट का सामना करना पड़ रहा है और बाजार का हर तबका रो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफइंडिया (आरबीआई) के पूर्व गनर्वनर एवम् पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी एक बीमार सोच कला और मनहूस कदम बताया तो वहीं आरबीआई के पूर्व गनर्वर रघुराम राजन ने नोटबंदी और जीएसटी को देश की आर्थिक वृद्धि की राह में ऐसी दो बड़ी अड़चने बताया, जिन्होंने पिछले वर्ष अर्थव्यवस्था में तेजी को प्रभावित किया। विपक्ष ने इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया।

नोटबंदी की तीखी आलोचना का जवाब देते हुए मोदी सरकार के बचाव में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने नोटबंदी से अर्थव्यवस्था की मजबूती, टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ने और काले धन पर लगाम जैसे फायदे बताए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बदौलत विकास किया गया। परन्तु दोनों ने नोटबंदी के घोषित उद्देश्यों की कोई चर्चा नहीं की और लोगों का इससे ध्यान भटकाने का प्रयास किया। मोदी सरकार के झूठ का सबसे बड़ा सुबूत है कि मोदी सरकार के खजाने में भी धन की कमी आ गई है। इसलिए सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए आरबीआई पर दबाव बनाये हुए हैं कि आरबीआई अपने रिजर्व फंड से धन सरकार को ट्रांसफर कर दे। मोदी सरकार ने वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था का विनाश कर दिया है ओर ऐसा लगता है कि विनाश का नाम बदलकर विकास कर दिया है।

संघ परिवार व प्रधानमंत्री मोदी तथा उनके प्रचारतंत्र ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के योगदान को नजरअंदाज करते हुए उनको एक विलेन के रूप में पेश करने की लगातार एक मुहिम चला रखी है तथा इतिहास को तोड़ मरोड़कर अपने मनमाफिक ढंग से लिखवाया जा रहा है। संघ परिवार ने हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का इस्तेमाल नेहरू को नीचा दिखाने के लिए किया जैसे कि उनमें आपस में कोई निजी दुश्मनी और और ऐसे मिथक प्रचार किए कि नेहरू ने अपने खानदान को राजनीति में आगे बढ़ाया तथा पटेल और सुभाष बोस को नजर अंदाज किया।

''खबर(दार) झरोखा-'वंशवादी' नेहरू ने इंदिरा को नहीं, सरदार पटेल को बेटी को संसद भेजा था!'' मैं संघ परिवार द्वारा प्रचारित झूठ का पर्दाफाश करते हुए ऐतिहासिक सच्चाई पेश की गई है कि तथाकथित वंशवादी नेहरू ने अपने जीते जी इंदिरा गांधी को कभी भी संसद का मुंह नहीं देखने दिया, जबकि पटेल के बेटे और बेटी दोनों एक साथ लोकसभा और राज्य सभा में थे। ऐसा संयोग वंशवादी नेहरू ने ही बताया था। नेहरु की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे न कि इंदिरा गांधी। 'बोस फाइल्स' से खुलासा हुआ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नेताजी की बेटी अनिता की मदद के लिए दो लाख रूपए का एक ट्रस्ट गठित किया था जिसे अनिता को लगातार वार्षिक आर्थिक मदद दी जाती थी। इस ट्रस्ट के प्रधानमंत्री नेहरू तथा पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.सी. राय ट्रस्टी थे। वास्तव में नेहरू, पटेल तथा नेताजी तीनों एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखते थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि छोटे व मझोले उद्योगों को एक घंटे से भी कम समय 59 मिनट में एक करोड़ रूपए तक का कर्ज मिल जायेगा, जिसका 'साहेब को 59 मिनट में कर्ज का आधे घंटे में किसान खुदकुशी और 15 मिनट में रेप से रिश्ता।' में विश्लेषण किया गया है। बैंकों से कर्ज के नाम पर रुपया निकलेगा लेकिन वह रूपया न वापिस लौटेगा और न कोई उद्योग, स्टार्टअप आदि शुरू हो पाएगा। लगता है कि एक करोड़ रूपए के कर्ज को बांटने का प्रावधान इसलिए किया जा रहा है कि इससे देश की लूट में हर किसी की हिस्सेदारी हो। स्वभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि यह कौनसी आर्थिक नीति है तथा स्वायत संस्थाओं का का क्या काम है? क्योंकि मोदी सरकार में कानून के दायरे में काम होता नहीं है।

2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है तो हरिद्वार में गंगा की अविरलता के लिए आंदोलन कर रहे प्रो. जी.डी. अग्रवाल को आशा बंधी थी कि मोदी जी गंगा के लिए जरूर कुछ करेंगे। परन्तु उन्हें निराशा हाथ लगी। प्रो. अग्रवाल ने मोदी जी को तीन पत्र लिखे लेकिन मोदी जी ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। गंगा की अविरलता के लिए मजबूर होकर अग्रवाल को अनशन पर बैठना पड़ा जो 111 दिन तक चला जब उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी 'जी.डी. अग्रवाल की मृत्यु: मोदी के नमामि गंगे प्रदर्शन का पर्दाफाश' में मोदी सरकार के गंगा प्रेम की असलियत की समीक्षा की गई है। मोदी के कार्यो से निराशा जाहिर करते हुए अग्रवाल ने लिखा था कि बीते चार सालों में मोदी सरकार ने गंगा से केवल लाभ कमाने और कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षणिक मामलों की समिति में शयद संघ समर्थित विचारों के लोगों का वर्चस्व स्थापित है जिससे वो पुस्तकें जो उनको पंसद नहीं है उनको सिलेबस से हटवाने में वे कामयाब हो जाते हैं, जिसकी 'गाय नहीं भैंस के दूध ने दी मजबूती, पाखंडी सन्यासी न पढ़ते हैं न पढ़ने देते हैं - कांचा अरलैय्या' में विस्तृत विवेचन किया गया है। दिल्ली विश्व विद्यालय के प्रतिबंधित पुस्तकों पर वार्ता की तथा साबित कर दिया कि विचारों को पाबंदी से नहीं मारा जा सकता। अहम संकल्प है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम क्या सत्ता तय करेगी तथा दलित, पिछलड़े आदिवासी, अल्पसंख्यक व महिलाओं पर लिखी पुस्तकें विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई जायेगी, तो फिर विश्वविद्यालय किस काम के लिए हैं?

पूरी दुनिया हवा में बढ़ते प्रदूषण से परेशान है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेनेवा में ग्लोबल पर पोल्यूशन बैठक आयोजित की जिसमें दुनिया के लगभग प्रत्येक देश को आमंत्रित किया गया था। परन्तु उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करना था और सत्ताधारी भाजपा ने देश भर में इसी दिन 'यूनिटी रन' रखा था, इसलिए भारत से आमन्त्रित तीनों केन्द्रीय मंत्री ;पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा व पेट्रोलियम मंत्री धमेन्द्र प्रधानद्ध जेनेवा नहीं पहुंचे जिसका 'सत्ता की फिक्र में पर्यावरण ताक पर' में विश्लेषण किया गया है। स्पष्ट है कि पांच राज्यों की विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार और भाजपा के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण समारोह और यूनिटी रन वायु प्रदूषण की रोकथाम से ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बजट ही बहुत कम रखा है जो इस बात का परिचायक है कि मोदी सरकार वायु प्रदूषण व लोगों के जीवन जीने के अधिकार के प्रति कितनी संवेदनशील है, जबकि दुनिया के बीस सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत के हैं।

सभी राज्यों में नौकरियों को जानबूझकर प्रक्रियाएं जटिल की जाती हैं जिससे मामला अदालतों में चलता रहे और नवयुवक नौकरी के लिए भटकते रहे। उत्तरप्रदेश में जनवरी 2018 में 68,500 शिक्षकों की भर्ती के समय शिक्षक भर्ती परीक्षा की पासिंग मार्क में बार-बार संशोधन करने से परेशान होकर उम्मीदवारों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया तो योगी सरकार की पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिसकी 'लखनऊ में लाठी खाने नौजवान और लोकतंत्र के कुछ सवाल' परतें खोली गई हैं। इन समस्याओं का हल केवल यही है कि अलग-अलग संघर्ष करने की बजाए, सभी छात्र मिलकर एक न्यायपूर्ण परीक्षा प्रणाली के लिए संघर्ष करें।

महात्मा बुद्ध की 128 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाने पर 130 करोड़ रूपए, खर्च करने पर तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाने पर 3000 करोड़ रूपए देने पर 'फक इसीलिए,.....क्योंकि चौकीदार ही चोर है', मोदीजी द्वारा नोटबंदी के घोषित लक्ष्य प्राप्त न होने पर 'मिशन अकॉम्प्लिशड्! द आइडिया राज टू फाइंड द लाईट एट द एंड ऑफ द टनल-डिमोनिटाइजेशन', मोदी जी द्वारा ऐलान कि 59 मिनट में एक करोड रूपए तक का कर्ज मिल जायेगा पर 'तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं' तथा 2014 के चुनावों में मोदीजी द्वारा मां गंगा ने उन्हें बुलाया है कहने पर 'जो कहता था खुद को मां गंगा का लाल, वो तो निकला उद्योगपतियों का दलाल' कार्टूनों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।